ELECTRICITY EMPLOYEES' FEDERATION OF INDIA
B.T. Ranadive Bhawan, 13A, Rouse Avenue, New Delhi-110 002
Telefax : +91 11 23219670 W : eeficentre.org E : eefederation@gmail.com
President : **Elamaram Kareem** (Ex-M.P.) E : elamaramkareem2010@gmail.com
General Secretary : **Prasanta N Chowdhury**
E : prasantanc1@gmail.com

No. Date :
9वां/प्रेस/03/2024 **31.12.2024**

प्रेस विज्ञप्ति
बिजली कर्मियों की कौंधः निजीकरण के खिलाफ 'एक–घंटे की देशव्यापी हड़ताल कारवाई'

इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (ईईएफआई), हजारों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को 31 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से 01 बजे तक देश भर में "एक घंटे का काम बंद" रखने के लिए बधाई देता है। देश के बिजली कर्मचारियों ने संघर्षरत चंडीगढ़ यूटी और यूपी बिजली कर्मचारियों को एकजुटता और समर्थन देने के लिए ईईएफआई के प्रस्तावित और बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) के द्वारा ग्रहित सिद्धांत अनुसार इस हड़ताल कारवाई में भाग लिया। इस अभूतपूर्व अनूठी सांकेतिक हड़ताल कारवाई के साथ राज्यों की राजधानियों में बड़े पैमाने पर लामबंदी की गई और भारत के माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे गए।

राष्ट्रीय स्तर की यह कार्रवाई चंडीगढ़ और यूपी के बिजलीकर्मियों के चल रहे निजीकरण विरोधी बहादुराना संघर्ष से जुड़ी हुई है। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन अपनी अनुकरणीय सार्वजनिक बिजली उपक्रम को एक निजी कंपनी को औने–पौने दाम पर उपहार में देने के लिए इतना बेताब हो गया है कि 250 करोड़ रुपये के औसत सालाना मुनाफे वाले उपक्रम की बोली बिना उचित मूल्यांकन के मात्र 174.63 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर बेईमानी से लगाई गई। निजीकरण के ऐसे ही हमले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) पर भी किए गए हैं। इन दोनों उपक्रमों को अभी भी 66,000 करोड़ रुपये के लंबित बिलों का संग्रह करना है, जो कि अगर निजी कंपनियों को सौंप दिए जाते हैं तो ये भारी रकम भी निजी खजाने में जुड़ जाएंगे। आश्चर्यजनक रूप से, यह खबर आ रही है कि इनकी प्रस्तावित आरक्षित बोली मूल्य केवल 1,500 करोड़ रुपये है!

आम जनता और जाहिर तौर पर बिजली कर्मचारी हर दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। हितधारकों की बात सुनने के बजाय, चंडीगढ़ प्रशासन और यूपी सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है और किसी भी तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन हमलों के जवाब में, बिजली कर्मचारियों ने बहादुरी से खड़े होकर बिजली क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक घंटे का काम बंद करने का आह्वान किया।

2.30 बजे तक प्राप्त हुई शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, केरल में 24,000 से अधिक यानि कुल बिजली कर्मचारियों में से 90 प्रतिशत ने इस कारवाई में हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के 63 दफ्तरों में लगभग 10,000 ने हड़ताल में भाग लिया। तमिलनाडु में जनरेशन स्टेशनों सहित 8,400 कर्मी हड़ताल में शामिल हुए। पंजाब में लगभग 10,000 कर्मचारियों, हरियाणा में 3500 कर्मचारियों, आंध्र प्रदेश में 500 और असम में 350 कर्मचारियों ने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना के 31 जिलों में लगभग 4,000 कर्मचारियों ने हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया। जम्मू–कश्मीर में बिजली कर्मचारी भारी बर्फबारी के बीच सड़कों पर उतर आए। अन्य राज्यों से भी हड़ताल में भारी भागीदारी की खबरें आ रही हैं।

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (एआईआरटीडब्ल्यूएफ) के बैनर तले सड़क परिवहन क्षेत्र के मजदूरों ने भी एक साथ ही पूरे देश में बिजली कर्मियों के साथ एकजुटता कार्रवाई में भाग लिया है। इसके साथ ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन (एआईएसजीईएफ) ने भी अपनी एकजुटता प्रकट की है। भारत के केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने देश के पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन को संघर्षरत बिजली कर्मचारियों के साथ सक्रिय रूप से एकजुटता में खड़े होने का आह्वान किया है।

यह देशव्यापी कार्रवाई बिजली कर्मचारियों के सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा के अपने दृढ़ संकल्प को दिखाती है। जाहिर है कि सबसे रणनीतिक हड़ताली शक्ति वाले बिजली कर्मचारी इस संघर्ष को किसी भी हद तक आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अगर केंद्र सरकार सार्वजनिक बिजली उपक्रमों के अपने जन–विरोधी निजीकरण के प्रयासों को नहीं रोकती है, तो देश के बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल की कार्रवाई के चरण तक संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

जारीकर्ता

Chow P. N.
(प्रशांत एन चौधरी)
महासचिव